योजना का सारांश (मार्च 2026)

चार स्तंभों के माध्यम से विकसित भारत को आगे बढ़ाना

परिचय

वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में विकसित भारत को चार स्तंभों पर आधारित किया गया है: युवा, महिलाएँ, किसान एवं निर्धन। इसमें कौशल विकास, समावेशन, ग्रामीण संक्रमण एवं सामाजिक सुरक्षा को व्यापक विकास का आधार माना गया है।

विकास के प्रेरक के रूप में युवा एवं महिलाएँ

- युवाओं के लिए बजट में कौशल विकास, रोजगार क्षमता, उद्यमिता एवं शिक्षा-उद्योग के बीच बेहतर तालमेल को प्राथमिकता दी गई है।
- औद्योगिक गलियारों के पास स्थित पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप का उद्देश्य शिक्षा, नवाचार एवं बाजार की माँग के बीच सेतु बनाना है।
- 10,000 करोड़ रुपए का एम.एस.एम.ई. (MSME) ग्रोथ फंड उन फर्मों को विकसित करने का प्रयास करता है जो विस्तार योग्य हैं और उन्हें अग्रणी उद्यमों में तब्दील करना चाहते हैं।
- बजट में आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गयी है और एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है।
- कॉर्पोरेट मित्र छोटे शहरों में MSMEs को GST, अनुपालन, बही-खाता एवं फाइलिंग में सहायता प्रदान करेंगे।
- महिलाओं के लिए यह बजट उद्यमिता, श्रम भागीदारी, शिक्षा तक पहुँच और जमीनी स्तर पर बाजार संबंधों को बढ़ावा देता है।
- 'सी मार्ट्स (SHE Marts)' से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच में सुधार होगा।
- प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए समर्पित छात्रावासों का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) संस्थानों में छात्राओं के नामांकन को बढ़ाना है।

किसान एवं ग्रामीण उत्पादन प्रणालियाँ

- किसानों के लिए बजट में उच्च मूल्य वाली, विविध एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम कृषि को मुख्य फसलों पर निर्भर खेती से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) 'एग्री स्टैक' और 'आईसीएआर सलाहकार प्रणालियों' का उपयोग करके बहुभाषी व एआई-संचालित कृषि मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- पूर्वोत्तर में प्राथमिकता वाली फसलों में नारियल, कोको, काजू, चंदन, मेवे एवं वृक्षों की फसलें शामिल हैं।
- डेयरी, पोल्ट्री एवं संबंधित क्षेत्रों को ऋण-आधारित समर्थन, पशु चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और एकीकृत मूल्य-शृंखला विकास प्रदान किया गया है।
- मत्स्यन नीति 500 जलाशयों, अमृत सरोवरों, स्टार्टअप्स एवं एफ.एफ.पी.ओ. एकीकरण के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा देती है।
- ई.ई.जेड. (EEZ) में पकड़ी गई मछलियों के लिए शुल्क-मुक्त व्यवस्था का उद्देश्य समुद्री खाद्य की प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।
- भंडारण, प्रसंस्करण एवं मूल्य-शृंखला में किए गए निवेश का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान व कमजोर बाजार संबंधों को कम करना है।
- नारियल, काजू एवं कोको के लिए कार्यक्रम भी उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात-उन्मुख प्रसंस्करण को लक्षित करते हैं।

गरीब एवं समावेशी विकास ढाँचा

- गरीबों के लिए यह रणनीति सामाजिक सुरक्षा को आजीविका एवं औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश के रास्तों के साथ जोड़ती है।
- VB-G RAM G से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार होगा और 125 दिनों तक के गारंटीयुक्त कार्य का वादा है।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रतिमाह 5 किलो निःशुल्क अनाज प्रदान करके खाद्य सुरक्षा को जारी रखती है।
- आंगनवाड़ी एवं शिशु देखभाल सेवाओं के माध्यम से सशक्त पोषण योजनाएँ मातृ एवं शिशु विकास परिणामों को लक्षित करती हैं।
- किफायती आवास के लिए धन आवंटन में भारी वृद्धि हुई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन में 69% और शहरी क्षेत्रों के लिए 179% की वृद्धि हुई है।
- यह लेख समावेशी विकास, सहभागी विकास और व्यवस्थागत झटकों के प्रति लचीलेपन के लिए इन चारों स्तंभों को आपस में जोड़ता है।
- बजट का व्यापक लक्ष्य जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक क्षमता और सामाजिक स्थिरता में परिवर्तित करना है।
- यह सबका साथ, सबका विकास को व्यापक 'विकसित भारत' रोडमैप के मार्गदर्शक तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

यह लेख बजट को क्षमता, समावेशन एवं आजीविका सुरक्षा पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक खाका के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य दावा यह है कि विकसित भारत के लिए लोगों, उत्पादन प्रणालियों और सुरक्षा में एक साथ निवेश की आवश्यकता है।

मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सशक्तीकरण

परिचय

इस लेख में बजट 2026–27 के उन उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जो कर अनुपालन को आसान बनाते हैं, लेन-देन संबंधी बाधाओं को कम करते हैं और मध्यम वर्ग के आय प्रवाह को समर्थन देते हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि ये कदम सरकार की व्यापक राजकोषीय योजना को प्रभावित किए बिना परिवारों को सशक्त बनाते हैं।

कर राहत और राजकोषीय संतुलन

- बजट 2026–27 में मौजूदा दरों, स्लैबों एवं छूटों को जारी रखा गया है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों के साथ मध्यम वर्ग को राहत देने के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।
- 1 अप्रैल, 2025 से नई व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो गई।
- नई कर व्यवस्था में कर स्लैब में बदलाव के कारण राजस्व संग्रह में ₹1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आई, जिससे राजकोषीय स्थिति प्रभावित हुई।
- इस लेख में बताया गया है कि 22 सितंबर, 2025 से जी.एस.टी. दर में कमी के कारण राजस्व संग्रह पर लगभग ₹48,000 करोड़ का प्रभाव पड़ा है।
- सरकार अभी भी 2026–27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम है।

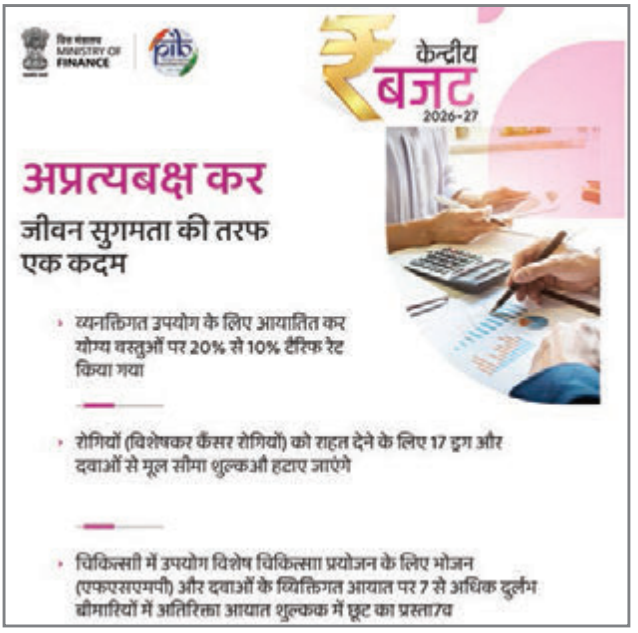

अनुपालन सुगमता एवं निवेशकों की सुविधा

- संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 12 महीने तक बढ़ा दी गई है जिससे अगले वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा।

- निवेशक म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों एवं लाभाँश आय के लिए डिपॉजिटरी को फॉर्म 15जी/15एच जमा कर सकते हैं।
- छोटे करदाता आयकर अधिकारियों के समक्ष कम या शून्य टी.डी.एस. (TDS) प्रमाणपत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकते हैं।
- एक बार की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना आगे के कर, जुर्माना एवं अभियोजन से छूट प्रदान करती है।
- बायबैक कराधान में अब प्राप्त आय को पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाता है जिससे विशेष रूप से छोटे गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों को लाभ होता है।

लेन-देन की निम्न लागत एवं जीवनशैली में राहत

- एम.ए.सी.टी. (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है।
- एल.आर.एस. (LRS) के तहत टी.सी.एस. (TCS) 10 लाख रुपए से अधिक की शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी भुगतानों पर घटकर 2% हो जाता है।
- विदेशी टूर पैकेजों पर टी.सी.एस. घटकर 2% हो गया है जिससे रिफंड पर निर्भरता व नकदी अवरोध कम हो गया है।
- विदेश से वापस लौटने पर लैपटॉप क्लैरिटी एवं घरेलू सामान पर राहत के साथ ड्यूटी-फ्री छूट ₹75,000 तक बढ़ गई है।
- सीमा शुल्क के युक्तिकरण से 17 कैंसर दवाओं पर शुल्क हटा दिया गया है और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाओं के आयात पर छूट दी गई है।

निष्कर्ष

यह लेख बजट को मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज के रूप में प्रस्तुत करता है जो दिखावटी रियायतों के बजाय परेशानियों को कम करने पर अधिक केंद्रित है। इसका मुख्य संदेश यह है कि बेहतर अनुपालन, निम्न कर दरों एवं लक्षित राहतों के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है।

आर्थिक गुणक के रूप में अवसंरचना

परिचय

यह लेख अवसंरचना को विकास, उत्पादकता, संपर्क एवं दीर्घकालिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के एक उच्च-प्रभावशाली चालक के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि बजट 2026–27 पूंजीगत व्यय-आधारित विकास को बनाए रखते हुए एकीकरण, रसद दक्षता एवं भविष्य के लिए तैयार विकास को बढ़ावा देता है।

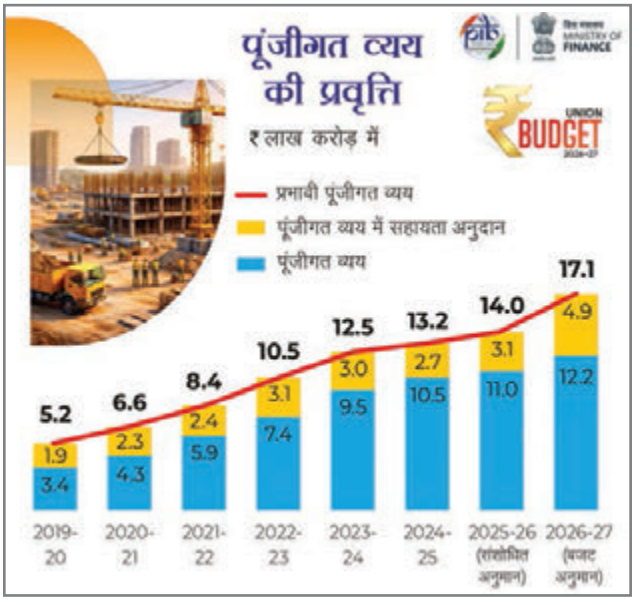

विकास के गुणक के रूप में अवसंरचना

- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014–15 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026–27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- बुनियादी ढाँचा से मटैरियल एवं श्रम की प्रत्यक्ष माँग सृजित होती है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार, बुनियादी ढाँचे पर किया गया खर्च जी.डी.पी. के 2.5 से 3.5 गुना तक का गुणक प्रदान करता है।

- बेहतर बुनियादी ढाँचा रसद लागत को कम करता है, कनेक्टिविटी में सुधार करता है और अधिक कुशल व्यावसायिक संचालन को सक्षम बनाता है।
- अधिक पूंजीगत व्यय से निजी निवेश भी आकर्षित होता है, प्रतिस्पर्द्धात्मकता मजबूत होती है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।

पैमाना, एकीकरण एवं क्षेत्रीय विस्तार

- राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना का विस्तार 6,835 परियोजनाओं से बढ़कर 9,000–13,000 परियोजनाओं तक हो गया है जिनका मूल्य ₹185 लाख करोड़ है।
- मार्च 2024 तक एन.आई.पी. (NIP) परियोजनाओं में से 20% पूरी हो चुकी थीं और 46% विकास के अधीन थीं।
- पीएम गति शक्ति ने एकीकृत नियोजन के लिए 58 मंत्रालयों और 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने साथ शामिल किया है।
- इस मास्टर प्लान में 1,700 से अधिक डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया और ₹13.59 लाख करोड़ की 293 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।
- बजट 2026–27 में पाँच वर्षों में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रस्ताव है।
- विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि में रेलवे के लिए 2.92 ट्रिलियन रुपए और सड़कों व राजमार्गों के लिए 3.09 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं।

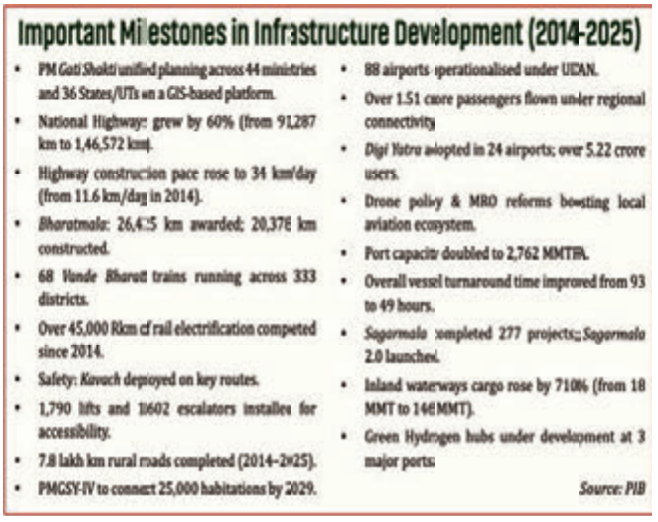

उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

- वर्ष 2014 से राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि हुई है और निर्माण की गति बढ़कर प्रतिदिन 34 किलोमीटर हो गई है।
- उडान (UDAN) के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया, जबकि बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी होकर 2,762 MMTPA हो गई और टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ।
- 45,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक रेल विद्युतीकरण और 68 वंदे भारत ट्रेनों का कार्य व्यापक नेटवर्क आधुनिकीकरण को दर्शाता है।
- परियोजना क्रियान्वयन अभी भी कमजोर डी.पी.आर., कठोर खरीद प्रक्रिया, विवादों के कारण होने वाली देरी और तैयारियों में कमियों से ग्रस्त है।
- सड़क, बिजली, परिवहन और डिजिटल नेटवर्क में प्रगति के बावजूद ग्रामीण एवं अंतिम-मील कनेक्टिविटी असमान बनी हुई है।
- तेजी से हो रहे अवसंरचना विस्तार में पारिस्थितिक स्थिरता का भी ध्यान रखना चाहिए और वनों की कटाई, क्षरण एवं सामाजिक संघर्ष से बचना चाहिए।

निष्कर्ष

यह लेख बुनियादी ढाँचे को भारत की मध्यम अवधि की विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता रणनीति की रीढ़ मानता है। इसमें मुख्य चेतावनी यह है कि बेहतर क्रियान्वयन, समावेशन एवं वहनीयता के बिना केवल व्यापक स्तर ही पर्याप्त नहीं है।

भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था- भारतीय क्रिएटिव प्रौद्योगिकी संस्थान की भूमिका

परिचय

इस लेख में तर्क दिया गया है कि भारत ए.वी.जी.सी. (AVGC) शिक्षा एवं रचनात्मक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमी में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। इसमें बजट द्वारा समर्थित आई.आई.सी.टी. (IICT) के नेतृत्व वाली प्रयोगशालाओं के विस्तार को रचनात्मकता, रोजगार, नवाचार एवं सांस्कृतिक आत्मविश्वास को जोड़ने वाला एक रणनीतिक कदम बताया गया है।

AVGC एक रणनीतिक विकास क्षेत्र के रूप में

- भारत के AVGC क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है जिसमें कलाकारों, डिजाइनरों, इंजीनियरों और इमर्सिव-मीडिया विशेषज्ञों की माँग बढ़ रही है।
- उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, भारत के AVGC उद्योग को 2030 तक लगभग दो मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
- अब इस क्षेत्र में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सआर (XR), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल-टाइम इंजन शामिल हैं।
- भारत का मीडिया इकोसिस्टम ओटीटी प्लेटफॉर्म, किफायती डेटा एक्सेस और बढ़ती डिजिटल खपत के माध्यम से विकसित हुआ है।
- इस लेख में कहा गया है कि भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माता बनना चाहिए, न कि केवल बैक-एंड क्रिएटिव सर्विसेज प्रदाता।

IICT और राष्ट्रव्यापी कौशल विस्तार

- बजट सहायता से आई.आई.सी.टी. मुंबई 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ए.वी.जी.सी. क्रिएटर लैब स्थापित करने में सक्षम होगा।
- जुलाई 2025 में शुरू किया गया पहला IICT परिसर, पेशेवर उत्पादन वातावरण और इमर्सिव स्टूडियो का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है।
- आई.आई.सी.टी. द्वारा एनीमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, पोस्ट-प्रोडक्शन और एक्सटेंडेड रियलिटी को कवर करने वाले 18 उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है।
- अल्पकालिक कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को रचनात्मक कार्यप्रवाहों में एकीकृत करते हैं जिनमें रेंडरिंग, प्रक्रियात्मक निर्माण एवं एआई-सहायता प्राप्त उत्पादन शामिल हैं।
- IICT ने गेमिंग, डिजिटल आर्ट एवं इंटरैक्टिव मीडिया के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाला एक इनक्यूबेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया है।
- यह पहल रचनात्मक प्रौद्योगिकियों को विशिष्ट या सहायक गतिविधियों के बजाय मुख्य आर्थिक चालक के रूप में देखती है।

शिक्षा, नवाचार और आगे की राह

- स्कूल की प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रारंभिक अनुभव संज्ञानात्मक क्षमताओं, आत्मविश्वास, आत्म-अभिव्यक्ति एवं सहयोगात्मक समस्या-समाधान को मजबूत कर सकता है।
- यह लेख अंत:विषयक शिक्षण पर जोर देता है, जहाँ प्रौद्योगिकी, स्टोरीटेलिंग, डिजाइन एवं उद्यमिता रोजगार क्षमता को मजबूत करते हैं।
- फिल्म सिटी के एक स्थायी परिसर की योजना बनाई जा रही है जो अनुसंधान एवं नवाचार प्रयोगशालाओं के साथ एक एकीकृत रचनात्मक-तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- स्टूडियो एवं प्लेटफॉर्म के साथ उद्योग साझेदारी से पाठ्यक्रम वैश्विक मानकों और इंटर्नशिप के अनुरूप बने रहेंगे।
- ऑरेंज इकोनॉमी को दीर्घकालिक मूल्य तब मिलता है जब क्रिएटर कहानियों, पात्रों एवं संपत्तियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार बनाए रखते हैं।
- भविष्य की सफलता के लिए कार्यान्वयन की गुणवत्ता, संकाय विकास, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और उद्योग से निरंतर प्रतिक्रिया आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह लेख AVGC (ए.वी.जी.सी.) पहल को महज कौशल विकास की पहल से कहीं अधिक, राष्ट्र निर्माण में एक निवेश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मूल संदेश यह है कि भारत के युवा संरचित रचनात्मक-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से सांस्कृतिक कल्पना को आर्थिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं।

AI और वास्तविक नियंत्रणकर्ता

परिचय

इस लेख में तर्क दिया गया है कि एआई प्रशासन (AI Governance) केवल प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है बल्कि सत्ता, जवाबदेही एवं संस्थागत नियंत्रण के बारे में भी है। इसमें बजट 2026–27 को सतर्क, क्षमता-केंद्रित एवं व्यावहारिक बताया गया है किंतु फिर भी इसमें प्रशासन से जुड़े मूलभूत प्रश्न अनसुलझे रह गए हैं।

बजट का एआई दृष्टिकोण और संस्थागत तर्क

- बजट 2026–27 एआई के प्रचार से बचता दिखता है और इसके बजाय सुर्खियाँ बटोरने वाले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के स्थान पर क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देता है।
- इसका दृष्टिकोण मजबूत कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचे, बेहतर डेटा सिस्टम और व्यापक डीप-टेक क्षमता पर आधारित है।
- इसमें कौशल विकास एवं पुनः कौशल विकास (Skilling and Reskilling) पर भी जोर दिया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के लिए एआई व मशीन लर्निंग प्रशिक्षण शामिल है।
- बजट में एआई को कृषि जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जहाँ परिणामों का अधिक स्पष्ट रूप से परीक्षण किया जा सकता है।
- वित्त मंत्री ने रोजगार, कौशल एवं शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों पर नजर रखने के लिए एक स्थायी समिति का प्रस्ताव रखा।
- इससे पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने और श्रमिकों को नौकरियों एवं प्रशिक्षण के अवसरों से जोड़ने की मंशा का भी संकेत मिलता है।

उपयोग मामले, निर्भरताएँ एवं शासन संबंधी जोखिम

- भारत-विस्तार किसानों को सलाह देने के लिए एग्री स्टैक और आईसीएआर प्रणालियों को संयोजित करने वाला एक बहुभाषी एआई उपकरण है।
- दिव्याँग सहारा योजना के तहत सहायक प्रौद्योगिकी माट्र्स के माध्यम से एआई-सक्षम सहायक उपकरणों का प्रस्ताव किया गया है।
- इस लेख में तर्क दिया गया है कि शुरुआती चरण में AI को अपनाने वाले इसका उपयोग रणनीतिक रूप से करते हैं, जबकि देर से अपनाने वालों को पहले से मौजूद मानक, नियम एवं निर्भरताएँ विरासत में मिलती हैं।
- निर्भरता वेंडर की शर्तों, लेखापरीक्षण ढाँचे और बाह्य रूप से निर्धारित तकनीकी डिफॉल्ट के माध्यम से उत्पन्न हो सकती है।
- भारत में एआई के उपयोग को लेकर अभी भी डेटा की गुणवत्ता में खामियाँ, कमजोर कनेक्टिविटी और अविश्वसनीय शिकायत निवारण प्रणालियों जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।
- वहीं, स्वचालित प्रणाली जो दक्षता में सुधार करती है, कमजोर समूहों को चुपचाप बाहर भी कर सकती है।

नैतिकता, रोजगार एवं आगे की राह

- जब तक भर्ती और खरीद प्रणालियाँ प्रशिक्षित श्रमिकों की वास्तविक माँग पैदा नहीं करतीं हैं, तब तक कौशल विकास मात्र एक औपचारिकता बनकर रह सकता है।
- शिक्षा से रोजगार और उद्यम की पहल कम से कम प्रशिक्षण एवं नौकरियों के बीच के अंतर को स्वीकार करती है।
- लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि नैतिकता को शुरुआत से ही अंतर्निहित होना चाहिए, न कि तैनाती के बाद जोड़ा जाना चाहिए।
- इसमें गोपनीयता सुरक्षा उपायों, सहमति प्रोटोकॉल, पूर्वाग्रह ऑडिट, मानवीय निगरानी और कार्यात्मक अपील तंत्र की माँग की गई है।
- बजट 2026 में 'अभी क्षमता बढ़ाओ, बाद में विस्तार करो' की रणनीति अपनाई गई है, जिसे लेख विवेकपूर्ण मानता है।
- किंतु अगले चरण में निष्पक्षता, जवाबदेही एवं संस्थागत दृढ़ता से संबंधित कठिन सवालों के जवाब देने होंगे।

निष्कर्ष

यह लेख कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक तकनीकी विजय बनने से पहले शासन संबंधी चुनौती के रूप में देखता है। इसका अंतिम संदेश यह है कि एक आधुनिक राज्य का मूल्यांकन स्वचालन की गति से नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा करने की क्षमता से किया जाता है।

महिलाओं के लिए बजटीय प्रावधान

परिचय

इस लेख में तर्क दिया गया है कि बजट 2026–27 में आर्थिक एवं सामाजिक नीति के केंद्र में महिला सशक्तीकरण को रखा गया है। यह उच्च लैंगिक बजट को आजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए संस्थागत समर्थन से जोड़ता है।

लैंगिक बजट निर्धारण और आर्थिक भागीदारी

- वित्त वर्ष 2026–27 में लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए बजट कुल केंद्रीय बजट का 9.37% हो गया।
- लैंगिक समानता के उद्देश्य से तैयार किए गए बजट वक्तव्य में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 11.36% की वृद्धि है।
- DAY-NRLM का आवंटन बढ़कर ₹17,280 करोड़ हो गया, जिससे महिलाओं की ग्रामीण आजीविका और उद्यमिता नेटवर्क मजबूत हुए।
- इस मिशन ने देशभर में 10.05 करोड़ परिवारों को 90.9 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।
- उद्यमिता पहलों के माध्यम से लगभग 4.6 करोड़ महिला किसानों और 3.74 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
- 'सी माट्र्स' को स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और स्थानीय महिला उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

आजीविका, रोजगार एवं उत्पादक सहायता

- VB-G RAM G को आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए ₹44,506.49 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
- पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का लक्ष्य दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
- ई.पी.एफ.ओ. (EPFO) से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से यह योजना विनिर्माण और रोजगार सृजन करने वाले अन्य क्षेत्रों में औपचारिक भर्ती का समर्थन करती है।
- कृषोन्नति योजना का आवंटन बढ़कर ₹3,360 करोड़ हो गया है जो संशोधित अनुमानों से लगभग 65% अधिक है।
- महिला नेतृत्व वाले समूहों के साथ मूल्य-शृंखला संबंधों के माध्यम से मत्स्य पालन और तटीय आजीविका को सहायता प्रदान की जाती है।
- खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को ब्रांडिंग, प्रशिक्षण व बाजार तक पहुँच के लिए सहायता मिलती है।

स्वास्थ्य, जल, सुरक्षा एवं अनुकूल परिस्थितियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी की उपलब्धता को मजबूत करने और महिलाओं की श्रमसाध्य मेहनत को कम करने के लिए जल जीवन मिशन के आवंटन में अत्यधिक वृद्धि की गई है।
- इस मिशन का दायरा 2019 में 3.24 करोड़ परिवारों से बढ़कर जनवरी 2026 तक 15.79 करोड़ से अधिक होने की संभावना है।
- आर.सी.एच. (RCH) एवं एन.एच.एम. (NHM) फ्लेक्सी-पूल को अधिक सहायता प्राप्त होने से महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी देखभाल पर होने वाले खर्च में वृद्धि होगी।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवंटित राशि बढ़कर ₹1,014.05 करोड़ हो गई है जो गतिशीलता एवं सार्वजनिक भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है।
- महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तीकरण समर्थन के लिए मिशन शक्ति के लिए आवंटित धनराशि बढ़कर ₹3,200 करोड़ हो गई है।
- लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि कार्यान्वयन की गुणवत्ता ही यह निर्धारित करेगी कि बजटीय उद्देश्य वास्तविक परिणामों में परिवर्तित होता है या नहीं।

निष्कर्ष

यह लेख बजट 2026–27 को महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तुत करता है। अंत में, यह चेतावनी दी गई है कि स्थायी प्रभाव ईमानदार क्रियान्वयन, संस्थागत मजबूती और जवाबदेह वितरण पर निर्भर करता है।

टीबी मुक्त भारत की ओर भारत का रणनीतिक विकास

परिचय

यह लेख भारत की टीबी रणनीति को विखंडित रोग नियंत्रण से हटकर एकीकृत, जन-केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई की ओर एक बदलाव के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि भारत राजनीतिक नेतृत्व, नवाचार, पोषण सहायता और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से टीबी-मुक्त भारत की दिशा में प्रगति को गति दे रहा है।

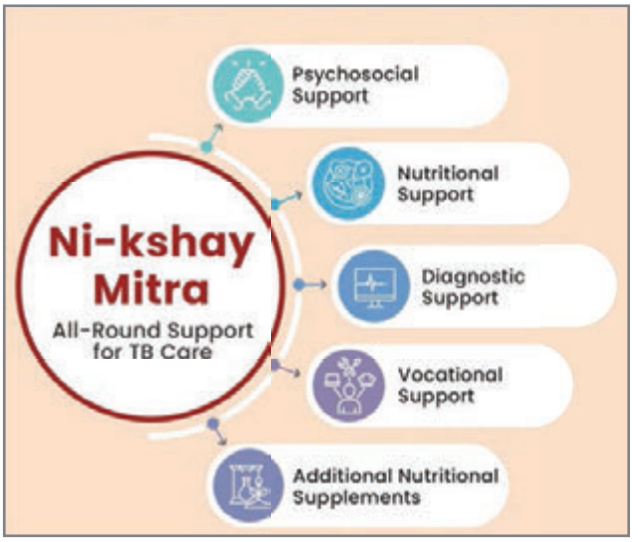

पैमाना, परिणाम एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण

- भारत में 2015 और 2024 के बीच टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई।
- टीबी के मामले प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 187 हो गए, जो वैश्विक गिरावट से लगभग दोगुना है।
- टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 25% की गिरावट आई है जो प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर 21 हो गई है।

- भारत ने 90% उपचार सफलता दर हासिल की है जो वैश्विक औसत 88% से बेहतर है।
- टीबी कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन 2015–16 और 2025–26 के बीच दस गुना बढ़ गया।
- रणनीति में विखंडित देखभाल से हटकर निदान, उपचार एवं सुरक्षा को जोड़ने वाली एक समग्र प्रणालीगत प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नवाचार, पहचान एवं उपचार का पुनर्रूपण

- नि–क्षय प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में ट्रैकिंग, केस नोटिफिकेशन, एनालिटिक्स एवं निजी क्षेत्र के एकीकरण को सक्षम बनाता है।
- सुनियोजित प्रोत्साहनों और सहभागिता के माध्यम से निजी क्षेत्र में टीबी के मामलों की सूचना 2013 से 24 गुना बढ़ गई है।
- 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 की शुरुआत देशव्यापी विस्तार से पहले 347 जिलों में हुई।
- 20 करोड़ से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों की जाँच की गई, जिसमें 28 लाख से अधिक टीबी के मामले सामने आए।
- भारत में अब 9,800 से अधिक आणविक परीक्षण केंद्र और 107 मान्यता प्राप्त टीबी कल्चर प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं।
- वर्ष 2024 में भारत ने बीपीएएलएम (BPaLM) उपचार पद्धति को अपनाया, जिससे कम समय में और सुरक्षित उपचार के साथ डी.आर.टी. की देखभाल में सुधार हुआ।

पोषण, सामुदायिक सहयोग एवं वैश्विक प्रासंगिकता

- नि–क्षय पोषण योजना ने पोषण सहायता को संस्थागत रूप दिया, जिसके तहत मासिक हस्तांतरण राशि को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया।
- नवंबर 2025 तक 1.39 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹4,538 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी थी।
- 7 लाख से अधिक नि–क्षय मित्रों ने टीबी से प्रभावित व्यक्तियों को 49 लाख से अधिक पोषणयुक्त खाद्य टोकरियाँ वितरित कीं।
- वर्ष 2025 में 30,000 से अधिक निर्वाचित नेताओं ने संबंधित पहलों में भाग लिया, जिससे जन भागीदारी एवं स्थानीय जवाबदेही को बढ़ावा मिला।
- टीबी मुक्त पंचायत पहल में ग्राम पंचायतों व स्थानीय नेताओं को उन्मूलन के केंद्र में रखा गया है।
- यह लेख भारत के मॉडल को वैश्विक दक्षिण के एक ऐसे खाके के रूप में प्रस्तुत करता है जो व्यापकता, साक्ष्य एवं सहभागिता पर आधारित है।

निष्कर्ष

यह लेख भारत के टीबी मिशन को केवल रोग नियंत्रण से कहीं अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत करता है। यह एकीकृत जन कार्रवाई का एक आदर्श उदाहरण है। इसका मुख्य संदेश यह है कि टीबी उन्मूलन के लिए प्रणाली, विज्ञान, पोषण एवं लोगों की निरंतर भागीदारी आवश्यक है।

जनहित के लिए नवाचार- कृषि परिवर्तन की पुनर्कल्पना

परिचय

यह लेख तर्क देता है कि भारत का कृषि रूपांतरण अब कैलोरी सुरक्षा से परे जाकर नवाचार को जनहित से जोड़ता है। यह कृषि को 2047 तक विकसित भारत की ओर एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, विकेंद्रीकृत एवं किसान-केंद्रित मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है।

कृषि प्रतिमान में बदलाव

- कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के तनाव और खाद्य माँग के दबाव का सामना कर रहा है जिससे लचीले कृषि-तकनीक नवाचार की आवश्यकता तेजी से बढ़ती जा रही है।
- भारत की जनसंख्या 18% है किंतु भूमि केवल 2.4% है जिससे उत्पादकता एवं दक्षता की चुनौती और भी बढ़ जाती है।
- यह क्षेत्र लगभग 50% कार्यबल का समर्थन करता है किंतु सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान केवल लगभग 18% है जो संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है।
- खाद्यान्न उत्पादन 1970–71 में 108.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024–25 में 357.73 मिलियन टन हो गया।
- यह लेख खाद्य सुरक्षा से हटकर पोषण, आय एवं वहनीयता सहित समृद्धि सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

नीतिगत समर्थन और प्रौद्योगिकी एकीकरण

- वैश्विक कृषि-तकनीक बाजार 2024 में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
- सटीक (परिशुद्ध) कृषि में पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए जी.पी.एस., सेंसर एवं आई.ओ.टी. उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- यह लेख जलवायु-अनुकूल उत्पादकता उपकरणों के रूप में किसान ड्रोन, लचीली फसल किस्मों और जैव प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालता है।
- ई-नाम (e-NAM) और डिजिटल अवसंरचना बाजार के विखंडन को कम करती है जिससे राज्यों में दूरस्थ किसानों के लिए खरीदारों तक पहुँच का विस्तार होता है।

- भारत-विस्तार द्वारा अनुकूलित व बहुभाषी कृषि निर्णय सहायता के लिए एग्री स्टैक और आईसीएआर सलाह को एकीकृत किया जाएगा।
- बजट 2026–27 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के साथ-साथ उच्च मूल्य वाली फसलों की रणनीतियों का समर्थन किया गया है।

जमीनी स्तर पर नवाचार और आगे की राह

- एन.आई.एफ.-इंडिया (NIF-India) पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए. तथा संबंधित ढाँचों के अंतर्गत किसानों के नवाचारों का दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन, संरक्षण और विपणन करता है।
- जमीनी स्तर के उपकरण श्रमसाध्य कार्यों में लगी महिला किसानों के लिए श्रम एवं लागत को कम करते हैं।
- धरमबीर कंबोज की प्रोसेसिंग मशीन 100 से अधिक उत्पादों को प्रोसेस करती है और अब 15 देशों में बेची जाती है।
- एचआरएमएन-99 (HRMN-99) सेब मैदानी एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगता है जिससे सेब की पारंपरिक खेती में ठंडक की अवधि पर निर्भरता की समस्या दूर हो जाती है।
- रियावान सिल्वर लहसुन और सदाबहार आम यह दर्शाते हैं कि किसानों के नेतृत्व में की गई प्रजनन प्रक्रिया से उत्पादन एवं बाजार तक पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।
- लेख में नुकसान को कम करने के लिए एग्री स्टैक डेटा को स्थानीय जलवायु-अनुकूल प्रथाओं के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया गया है।

निष्कर्ष

यह लेख भारत के कृषि भविष्य को स्वदेशी ज्ञान और डिजिटल अवसंरचना के समन्वय के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मूल संदेश यह है कि विकेंद्रीकृत नवाचार किसानों को निष्क्रिय उत्पादकों से सशक्त मूल्य-शृंखला भागीदार बना सकता है।

केंद्रीय बजट 2026–27

परिचय

यह लेख केंद्रीय बजट 2026–27 को कर्तव्य-आधारित ढाँचे के रूप में प्रस्तुत करता है जो राजकोषीय विवेक, विकास, क्षमता निर्माण और समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को संरचनात्मक परिवर्तन से जोड़ता है ताकि एक लचीले, प्रतिस्पर्द्धी एवं समावेशी विकसित भारत को शक्ति प्रदान की जा सके।

व्यापक (मैक्रो) आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा

- बजट 2026–27 में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 4.3% पर लक्षित किया गया है जिसमें ऋण अनुपात को कम करके 55.6% तक लाने का लक्ष्य है।
- गैर-ऋण प्राप्तियों की अनुमानित लागत 36.5 लाख करोड़ रुपये है जबकि कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाता है।
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है जिससे भविष्य की उत्पादन क्षमता और विकास की गति बनी रहेगी।
- बायोफार्मा शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन के माध्यम से रणनीतिक विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।
- 10,000 करोड़ रुपए की एस.एम.ई. (SME) विकास निधि और 'कॉर्पोरेट मित्र' प्रबंधकीय क्षमता और जोखिम पूंजी को सुदृढ़ करते हैं।

अवसंरचना, क्षमता एवं क्षेत्रीय विस्तार

- नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग एवं तटीय माल ढुलाई उपाय बहुआयामी रसद दक्षता को मजबूत करते हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड और आर.ई.आई.टी. (REIT) के नेतृत्व में परिसंपत्ति पुनर्चक्रण का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है।
- सात हाई-स्पीड रेल गलियारे विकास के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी-औद्योगिक एकीकरण को मजबूती मिलेगी।
- शिक्षा-रोजगार-उद्यम समिति, चिकित्सा केंद्रों, आयुष संस्थानों और पशु चिकित्सा कार्यबल में वृद्धि के माध्यम से मानव पूंजी का विस्तार होता है।
- 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ए.वी.जी.सी. लैब्स से ऑरेंज अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए तैयार कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

समावेशन, सरलीकरण एवं सामाजिक समानता

- भारत-विस्तार एग्री स्टैक और आईसीएआर के ज्ञान को एकीकृत करता है जो किसानों की आय के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम समर्थन का संकेत देता है।
- दिव्यांगजन कौशल योजना से आईटी, ए.वी.जी.सी., हॉस्पिटैलिटी और खाद्य एवं पेय पदार्थों के क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार होता है।
- निमहंस-2 और उन्नत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आपातकालीन देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हैं।
- नए आयकर अधिनियम में टी.सी.एस., टी.डी.एस., रिटर्न संशोधन को सरल बनाया गया है और कुछ कर अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
- डिजिटल सिंगल विंडो, जोखिम-आधारित स्कैनिंग, ए.ई.ओ. (AEO) लाभ और निर्यात-अनुकूल सीमा शुल्क सुधारों के माध्यम से व्यापार सुविधा का विस्तार हो रहा है।

निष्कर्ष

यह लेख बजट 2026–27 को एक रणनीतिक खाका के रूप में प्रस्तुत करता है जो व्यापक स्थिरता को समावेशी परिवर्तन के साथ संरेखित करता है। इसका मूल संदेश एक एकीकृत कर्तव्य ढाँचे के तहत लचीलेपन, क्षमता एवं समानता के साथ विकास करना है।